बिजनेस समाचार

आम्रपाली के बायर्स बोले, खून-पसीने की कमाई से बिल्डर ने खरीदी लग्जरी गाड़ियां

मुम्बई, 15 नवम्बर (ए)। आम्रपाली के हाथ से उनका ग्रेटर नोएडा स्थित 100 बेड का अस्पताल निकलने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इसे अटैच करने का आदेश दिया है। इसे बेचकर फ्लैट निर्माण के लिए फंड जुटाया जाएगा। बायर्स का कहना है कि उनके खून-पसीने की कमाई से बिल्डर ने लग्जरी गाड़ियां खरीदीं और अस्पताल, क्लब व दूसरे धंधों में पैसा खपा दिया। इसकी वसूली होनी चाहिए। आम्रपाली के बायर केके कौशल का आरोप है कि उनके पैसे से फ्लैट बनाने के बजाय अस्पताल बना दिया गया। इसे बेचा जाना चाहिए। इससे मिले पैसों से उनके घर जल्द तैयार किए जाएं। कोर्ट ने आम्रपाली से तीन हफ्ते के अंदर उनकी सभी 86 लग्जरी गाड़ियों के साथ-साथ ग्रुप की सभी कंपनियों के बीच ट्रांजेक्शन की सारी जानकारी देने को कहा है। 100 बेड का यह अस्पताल शहर के बीच ओमेगा-1 सेक्टर में प्राइम लोकेशन पर बना हुआ है। इससे सटे दो अन्य अस्पताल हैं और साथ ही यमुना अथॉरिटी का दफ्तर भी है। इसी से सटी हुई सेक्टर की मार्केट है। यह मुख्य सड़क के किनारे है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली ग्रुप के ग्रेटर नोएडा स्थित हॉस्पिटल सहित अन्य प्रॉपर्टी को अटैच करने का आदेश दिया है।

भारत ने अब तक किया 8 लाख टन चीनी निर्यात का अनुबंध

नई दिल्ली 15 नवम्बर (ए) ।चीनी के अधिशेष स्टॉक के बीच देश की चीनी मिलों ने पश्चिम एशिया और श्रीलंका जैसे देशों को करीब आठ लाख टन चीनी का निर्यात करने का अनुबंध किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कुल अनुबंधित मात्रा में से कच्ची चीनी 6 लाख टन है और शेष दो लाख टन साफचीनी है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि हम चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। चीन चीनी खरीदने को सहमत हुआ है और इंडोनेशिया के साथ भी बात चल रही है। अधिशेष स्टॉक को कम करने के लिएए सरकार ने घरेलू चीनी मिलों से 2018.19 विपणन वर्ष अक्टूबर, सितंबर में अनिवार्य रूप से 50 लाख टन चीनी निर्यात करने को कहा है तथा वह आंतरिक परिवहनए मालढुलाईए रखरखाव और अन्य शुल्कों के लिए आने वाले खर्च की भी भरपाई कर रही है।

मैगी के 10 खाली पैकेट के बदले एक पैकेट मुफ्त देगी नेस्ले

नई दिल्ली , 15 नवम्बर (ए)। दुनियाभर में प्लास्टिक पलूशन और इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले इंडिया ने अपने फ्लैगशिप ब्रांड्स मैगी नूडल्स के लिए 'रिटर्न स्कीम' शुरू की है। उपभोक्ता मैगी नूडल्स के 10 खाली पैकेट ले जाकर दुकान पर एक पैकेट मैगी मुफ्त में पा सकते हैं। यह स्कीम अभी देहरादून और मसूरी में शुरू हुई है। इसके जल्द दूसरे राज्यों में शुरू होने की उम्मीद है। यह तो अच्छा काम कर रहे हैं, प्लास्टिक का प्रमुखता से उपयोग करने वाली सभी कंपनियों को ऐसी कुछ न कुछ स्कीम लाकर लोगों को प्लास्टिक रिटर्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेस्ले इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देहरादून और मसूरी में शुरू किया गया है। इस क्षेत्र के करीब 250 रिटेलर्स इसका फायदा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके जरिए कंपनी का मकसद प्लास्टिक कचरे में कमी लाना है।

देश में बनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन ट्रायल के लिए तैयार

नई दिल्ली , 15 नवम्बर (ए)। देश में बनी पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन ञ-18 ट्रायल के लिए तैयार है। चेन्नै से लंबा सफर तय कर यह ट्रेन बुधवार को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पहुंच गई। सामान्य इंजन के सहारे ट्रेन को दिल्ली लाया गया है। अब इसका ट्रायल दिल्ली मुरादाबाद सेक्शन पर होगा। ट्रायल के समय पहली बार स्पीड काफी कम रहेगी। इसके बाद इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ले जाया जाएगा।

आरबीआई-केंद्र सरकार के बीच टला टकराव, गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के आसार नहीं : सूत्र

नई दिल्ली, 15 नवम्बर (ए)। आरबीआई-केंद्र सरकार के बीच चल रहा सबसे बड़ा विवाद अब हल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्ष मतभेद के दो अहम मुद्दों - लिक्विडिटी तथा क्रेडिट मामले पर हल तलाश करने के करीब पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार बोर्ड बैठक के दौरान आरबीआईगवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफा दे देने, जैसी अटकलें पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चल रही हैं, की संभावना नहीं है इसके साथ ही धारा-7 के भी इस्तेमाल करने के आसार नहीं है।

क्या है पूरा मामला : आपको बता दें कि कुछ हफ्तों से पहले ही केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई पर कर्ज के मामलों में नियमों में ढील और अतिरिक्त पैसा को सौंपने के लिए दबाव बना रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केंद्रीय बैंक का 1 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व रखा है उसको पाना चाहती है क्योंकि ताकि वह वित्तीय घाटे को पूरा कर इसका चुनाव में इस्तेमाल कर सके। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार नोटबंदी की 'त्रासदी पर पर्दा डालने और चुनावी मौसम में रेवड़ियां बांटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का खजाना लूटने को उतारू है।

नाकामियों को छिपा रही है सरकार : कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है मोदी सरकार आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित देखकर चुनाव से पहले अनैतिक ढंग से रेवड़ियां बांटने की कोशिश में हैय़इसलिए चुनावी मौसम में फायदा हासिल करने और अपने पूंजीपति मित्रों से प्यार की वजह से आरबीआई के खजाने को लूटने पर उतारू है। सिंघवी ने दावा किया कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए भी सरकार यह सब कर रही है और इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के जरिए गलत सूचना का प्रसार कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आरक्षित नकदी दर (सीआरआर) छह फीसदी है, लेकिन मोदी सरकार से इसे भी कम करना चाह रही है ताकि वह रिजर्व बैंक से पैसे ले सके।

जेट एयरवेज के अधिग्रहण की योजना पेश कर सकते हैं टाटा संस के चेयरमैन चंद्रशेखरन

मुंबई , 15 नवम्बर (ए)। देश का बड़ा बिजनस घराना टाटा आनेवाले दिनों में आसमान में यानी एविएशन इंडस्ट्री में भी राज करने की योजना में जुटा है। इसके तहत टाटा संस कर्ज के तले दबी जेट एयरवेज का अधिग्रहण करके सबसे बड़ी एविशन डील को अंजाम दे सकती है। खबर है कि टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन शुक्रवार को बोर्ड मेंबर्स के सामने जेट एयरवेज के अधिग्रहण का प्लान रख सकते हैं। अगर जेट में निवेश पर सहमति बनी, तो एविएशन इंडस्ट्री में टाटा का यह अब तक का तीसरा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके पहले वह एयर एशिया और विस्तारा में पैसे लगा चुकी है। अधिग्रहण किस प्रकार होगा, यह फिलहाल साफ नहीं है।

हालांकि, टाटा संस की मंशा जेट में 50त्न से ज्यादा शेयर खरीदकर उस पर मालिकाना हक पाने की है। इसमें चेयरमैन नरेश गोयल के पास 51 प्रतिशत शेयर है। टाटा संस गोयल के पास शेयरों का 25त्न जबकि बाकी शेयरधारकों के पास की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। इससे टाटा को जेट में कुल 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मेजॉरिटी कंट्रोल हासिल हो जाएगा। अभी जेट का मार्केट वैल्यू 2,928 करोड़ रुपये है और इस पर 86 अरब का कर्ज है। टाटा से डील के बाद वह वित्तीय संकट से बाहर आ सकेगी। आर्थिक संकट की वजह से वह अपने कर्मचारियों को सैलरी तक देने में सक्षम नहीं है। इस डील के बाद देश की एविएशन इंडस्ट्री में टाटा का शेयर बढ़कर 24 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें कि जेट एयरवेज के पास अपना कुल 124 जहाज हैं। घरेलू मार्केट में उसकी हिस्सेदारी कुल 16 प्रतिशत और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 14 प्रतिशत है। वहीं, विस्तारा और एयरएशिया इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में हिस्सेदारी 4-4 प्रतिशत है। इन दोनों कंपनियों के इंटरनैशनल फ्लाइट्स नहीं हैं। कहा जा रहा है कि टाटा विस्तारा और जेट एयरवेज को जोड़ भी सकती है। विस्तारा में टाटा की 51 प्रतिशत और सिंगापुर एयरलाइंस की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

पाम तेल आयात में नहीं होगा इजाफा!

मुम्बई, 15 नवम्बर (ए)। भारत का पाम तेल आयात नवम्बर से जनवरी के दौरान बढने के आसार नहीं हैं। भले ही इस जिंस के दाम 3 साल के निचले स्तर पर चले गए हों। व्यापारियों का कहना है कि अन्य तिलहन की पर्याप्त स्थानीय आर्पूति ने इस पर लगाम लगा दी है और नकदी संकट से भावी खरीदारों को धक्का पहुंचा है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल आयातक है और मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क कीमतों को प्रभावित करता है जो 2018 में अब तक करीब 20 प्रतिशत गिर चुकी हैं। व्यापारिक कम्पनी जी.जी. पटेल एंड निखिल रिसर्च कम्पनी के प्रबंध निदेशक गोविंदभाई पटेल ने कहा कि आयात में बढ़ौतरी नहीं होगी। नकदी संकट है और घरेलू तेल की उपलब्धता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 1 नवम्बर से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में देश का आयात औसतन 7,50,000 टन से 8,00,000 टन के बीच रह सकता है। पिछले 3 महीनों में लगभग यही स्तर दर्ज किए जाने का अनुमान लगाया गया था। पिछले विपणन वर्ष की इस अवधि में यह 7,58,000 टन था। व्यापारियों ने कहा कि गर्मियों में बोई गई सोयाबीन और मूंगफली जैसी तिलहनों की आर्पूति बाजार में आनी शुरू हो चुकी है और पिराई भी इस महीने रफ्तार पकड़ रही है। गर्मियों में बोई जाने वाली प्रमुख तिलहन सोयाबीन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 2018 में 20 प्रतिशत बढने की उम्मीद है।

कृष्णमूर्ति संभालेंगे फ्लिपकार्ट के सीईओ का पद

नई दिल्ली 15 नवम्बर (ए)। फ्लिपकार्ट समूह के सीईओ बिन्नी बंसल (37) के इस्तीफा के बाद अब कल्याण कृष्णमूर्ति कंपनी के सीईओ का पद संभालेंगे। अमेरिकी रिटेल कंपनी और फ्लिपकार्ट की नई पैतृक कंपनी वॉलमार्ट ने कहा कि अब इसमें मिंत्रा और जबांग को भी शामिल कर दिया गया है। मिंत्रा और जबांग के सीईओ अनंत नारायणन पद पर बने रहेंगे, लेकिन वह कृष्णमूर्ति को रिपोर्ट करेंगे। वहीं, समीर निगम फोनपे के सीईओ बने रहेंगे। कल्याण और समीर दोनों बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। सितंबर में खबरें आई थीं कि बिन्नी कंपनी के कामकाज में सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे।

पनामा पेपर्स वालों को ब्लैक मनी ऐक्ट के तहत नोटिस

मुंबई ● 15 नवम्बर (ए)।

पनामा पेपर्स के जरिए दुनिया के अमीरों की विदेश में कथित तौर पर छिपाई गई दौलत की जानकारी सामने आने के दो साल बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस लिस्ट में शामिल उन भारतीयों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी विदेशी संपत्ति और उस पर हासिल ब्याज और अन्य आमदनी का खुलासा नहीं किया है। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि टैक्स अधिकारियों और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की ओर से जांच किए जाने के बाद ये नोटिस जारी किए गए। इन नोटिसों में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स से कहा गया है कि वे 2015 से खुले विदेशी बैंक खातों, उन खातों के स्टेटमेंट और इन खातों में डेबिट/क्रेडिट एंट्रीज की पूरी जानकारी मुहैया कराएं। 2016 में फिल्म जगत के लोगों और कारोबारियों सहित करीब 500 भारतीयों के नाम पनामा पेपर्स में आए थे। ईडी और टैक्स डिपार्टमेंट ने उन एचएनआई को समन भेजकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिनके नाम इन पेपर्स में थे। अधिकतर एचएनआई ने दावा किया था कि उन्होंने भारत से बाहर प्रॉपर्टी खरीदने और निवेश करने के लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का सहारा लिया था। यह स्कीम किसी भी भारतीय को हर साल ढाई लाख डॉलर तक विदेश में निवेश करने की इजाजत देती है।सूत्रों ने बताया कि करीब 400 लोगों को नोटिस भेजे गए थे। अधिकतर लोगो ने पनामा में एक लॉ फर्म की सेवा लेकर ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में ऑफशोर अकाउंट्स खोले थे और उनमें पैसा जमा किया। उसके बाद लंदन, अमेरिका और दुबई में रियल एस्टेट और दूसरी चीजों में निवेश किया गया। एचएनआई से लिखित जवाब मिलने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी ने जांच में पाया कि सभी असेट्स और इन असेट्स से होने वाली पूरी इनकम का खुलासा नहीं किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नोटिस ब्लैक मनी (अनडिसक्लोज्ड इनकम एंड असेट्स) ऐक्ट के तहत भेजे गए हैं। इसमें दोषी पाए जाने पर 120 पर्सेंट टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर यह पाया गया कि गलत जानकारी दी गई थी तो 10 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। अशोक माहेश्वरी एंड असोसिएट्स एलएलपी के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने कहा, असेसमेंट के दौरान अगर यह पाया गया।

बंसल हॉस्पिटल में डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में व्याख्यान परिचर्चा सम्पन्न

भोपाल 15 नवम्बर (ए)। बंसल हॉस्पिटल में वर्ल्ड डायबिटीज डे के उपलक्ष्य में परिचर्चा एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमे डायबिटीज से ग्रसित व्यक्तियो एवं उनके घरवालो को डायबिटीज एवं इसकी जटिलताओं के बारे में जानकारी दी गई ।डायबिटीज एवं इससे जुड़ी भ्रान्तियों का जवाब विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया गया।

डॉ. अजीत वर्मा सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया कि डायबिटीज की बजह से पैरों में न्यूरोपेथी होने झुंझुनि, सुन्नपन एवं कमजोरी आ सकती है जिसकी रोकथाम ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखकर की जा सकती है। डॉ. विनीत रामनानी ने बताया कि डायबिटीज रेटीनोपैथी के कोई शुरुआती लक्षण नही होते है इसलिए नियमित रेटिना जांच जरूरी हैं। डॉ. विद्यानंद त्रिपाठी के अनुसार डायबिटीज वाले मरीजो में 7-10 साल बाद किडनी की समस्या हो सकती है इसलिए नियमित परीक्षण जरूरी है। डॉ. रितेश यादव ने बताया कि भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है इसलिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपनी शुगर नियंत्रण में रखे। डॉ. विनीता मेवाड़ा ने बताया कि डायबिटीज के नियंत्रण के लिए संतुलित आहार समयानुसार लेना आवश्यक है। इस मौके पर ष्टश्वह्र बंसल हॉस्पिटल डॉ. डी. के वर्मा एवं सचिन कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।

हिमालया ने अपना पहला ब्रांड कैम्पेन-''खुश रहो, खुशहाल रहो'' लॉन्च किया

नई दिल्ली 15 नवम्बर (ए)। भारत की अग्रणी वेलनेस कंपनी, द हिमालया ड्रग कंपनी ने आज अपना पहला ब्रांड कैम्पेन - 'खुश रहो, खुशहाल रहो' लॉन्च किया। इस कैम्पेन का उद्देश्य, '' हर घर में वैलनेस, हर दिल में खुशी'' को प्रचारित करना है। पिछले आठ दशकों में लाखों उपभोगताओं का विश्वास जीतने के बाद, हिमालया विज्ञान एवं शोध पर आधारित अपने हर्बल उत्पादों द्वारा ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समर्पित है। श्री फिलिप हेडन, सीईओ, द हिमालया ड्रग कंपनी ने कहा, ''आज हर्बल ब्रांड लोकप्रिय हो रहे हैं और ग्राहक हर्बल समाधानों को अपनी पहली पसंद बना रहे हैं। हिमालया अपने 500 से अधिक हर्बल उत्पादों के साथ उपभोगताओं का दिल जीतता आ रहा है। हिमालया ब्रांड के उद्देश्य को प्रदर्शित करने वाली हमारी पहली ब्रांड फिल्म का अनावरण करने में हमें गर्व हैं।'' इस अभियान के बारे में राजेश कृष्णमूर्ति, बिज़नेस डायरेक्टर- कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीज़न, द हिमालया ड्रग कंपनी ने कहा, ''इस ब्रांड फिल्म का सिद्धांत ग्राहकों की इस जानकारी पर आधारित है कि जब हमें समस्याओं का समाधान नहीं पता होता है, तो छोटी समस्याएं भी बड़ी प्रतीत होती हैं। हमारे ब्रांड का सिद्धांत है कि हम अपने हर्बल उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के द्वारा ग्राहकों की समस्याओं का समाधन करें और इस अभियान में यह बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है।

नोटबंदी के दौरान रिटर्न दाखिल न करने वाले मामलों के 'पीछे लगा' आयकर विभाग

नई दिल्ली, 15 नवम्बर (ए)। आयकर विभाग नोटबंदी के बाद रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 80,000 मामलों के 'पीछे लगा' है हालांकि, कर विभाग द्वारा इन लोगों को रिटर्न दाखिल करने का नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रगति मैदान में व्यापार मेले में आयकर विभाग के स्टॉल का उद्घाटन करने के बाद चंद्रा ने कहा कि विभाग ने 80 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है जिन्होंने पिछले तीन साल के दौरान अपना रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन इस बार अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। चंद्रा ने कहा कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद वास्तव में देश में कर आधार बढ़ाने में मदद मिली है।

इसके अलावा इससे प्रत्यक्ष करों से देश का शुद्ध राजस्व बढ़ा है। उन्होंने कहा, ''पिछले साल प्रत्यक्ष करों का योगदान 52 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष करों का 48 प्रतिशत था। कई साल बाद ऐसा हुआ है जबकि प्रत्यक्ष करों का योगदान अप्रत्यक्ष करों से अधिक रहा है। चंद्रा ने कहा कि आपके इस सवाल कि नोटबंदी से क्या मदद मिली, मैं कहूंगा कि पैसा बैंक खातों में आ गया। ऐसे में हमारे लिए यह पता लगाना आसान हो गया कि कितने लोगों ने नकदी जमा कराई जबकि उसके बारे में रिटर्न जमा नहीं कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद विभाग द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई के बारे में सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल और एसएमएस भेजे। इन लोगों ने उसके बाद रिटर्न दाखिल किए। चंद्रा ने कि नोटबंदी के बाद रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले तीन लाख लोगों को नोटिस भेजे गए। ये सांविधिक नोटिस थे। उसके बाद 2.25 लाख लोगों ने रिटर्न जमा कराया। 80,000 मामलों में रिटर्न जमा नहीं हुआ। विभाग ऐसे ही मामलों के पीछे लगा है।

जकरबर्ग की अधिकारियों को सलाह- सिर्फ एंड्रॉयड फोन करें यूज!

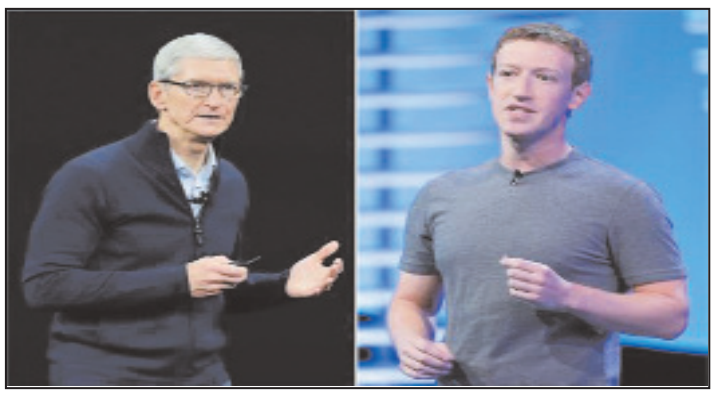

मुंबई 15 नवम्बर (ए)। ऐपल और फेसबुक के बीच की तल्खी बढ़ती जा रही है। फेसबुक की प्राइवेसी को लेकर ऐपल के सीईओ के बयान के बाद जकरबर्ग शायद नाराज हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने मैनेजमेंट टीम से सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करने को कहा है। न्यू यॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला जकरबर्ग ने ऐपल के सीईओ टिम कुक द्वारा की गई आलोचना की बाद लिया है।

इंटरव्यू में टिम कुक ने फेसबुक की आलोचना की। फिलहाल ये साफ नहीं है कि मार्क जकरबर्ग द्वारा मैनेजमेंट को सिर्फ एंड्रॉयड यूज करने सलाह के पीछे सीधे तौर पर टिम कुक का बयान ही है या फिर कोई और बात है। फेसबुक ने अब तक इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मार्क जकरबर्ग ने कंपनी के आला अधिकारियों से न यूज करने को कहा है।

फेसबुक यूजर्स के डेटा से पैसा कमाता हैः कुक : मार्च में भी टिम कुक ने फेसबुक की आलोचना की थी जब उनसे पूछा गया कि वो कैंब्रिज अनालिटिका मामले पर क्या करते अगर ये ऐपल में होता तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी स्थिति में आता ही नहीं। कुक का कहना था कि फेसबुक यूजर्स के डेटा से पैसा कमाता है और ऐपल ऐसा कभी नहीं करेगी। मार्क जकरबर्ग ने कुक के इस बयान के बाद इसे छिछला और वाहियात बयान बताया था।

पहले भी कई बार कर चुके आलोचना : टिम कुक ने इंटरव्यू में ये कहा कि हम आपकी पर्सनल लाइफ में घुस नहीं रहे हैं। प्राइवेसी ह्यूमन राइट है और यह सिविल लिबर्टी भी है'। ऐपल के सीईओ टिम कुक प्राइवेसी को लेकर सख्त माने जाते हैं और कई बार इन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फेसबुक की पॉलिसी की आलोचना खुल कर की है। इस वजह से हाल के कुछ महीनों से दोनों कंपनियों में एक तरह से तनाव का महौल है क्योंकि फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी टिम कुक के बयान का जवाब देते हुए निचले स्तर का कहा था।